

25 October 2024

असंगठित श्रमिकों के लिए ई-श्रम वन स्टॉप समाधान

संदर्भ: हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में 'ई-श्रम -वन-स्टॉप सॉल्यूशन' का अनावरण किया।

- यह ई-श्रम पोर्टल का अद्यतन संस्करण है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच को सरल बनाना, उनके पंजीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाना और उन्हें सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से लाभान्वित करने में सक्षम बनाना है।

ई-श्रम-वन स्टॉप सॉल्यूशन की मुख्य विशेषताएं:

- सरल पंजीकरण प्रक्रिया:** नई पहल एक सुव्यवस्थित पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करती है, जिससे असंगठित श्रमिकों के लिए पंजीकरण अधिक आसानी से किया जा सकता है।
- कनेक्टिविटी में सुधार:** यह प्लेटफॉर्म विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक सीधी पहुँच उपलब्ध कराता है, जिससे श्रमिक आसानी से लाभों की पहचान कर सकते हैं और उनके लिए आवेदन कर सकते हैं।
- एकीकृत डेटा:** विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के डेटा को समेकित करके, यह वन स्टॉप समाधान दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
- राज्य सरकारों के पोर्टल के साथ एकीकरण:** इसमें राज्य सरकार के पोर्टलों के साथ एकीकरण का उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार करना है, ताकि लाभ इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक प्रभावी रूप से पहुँच सके।

e-Shram One Stop Solution

A Single window for
Unorganized workers

Ensuring the availability of all key Social Security & Welfare Schemes



एकीकृत कल्याण योजनाएँ:

'वन स्टॉप सॉल्यूशन' में निम्नलिखित प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रम शामिल हैं:

- एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए)
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
- राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस)
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन

ई-श्रम पोर्टल के बारे में:

- अगस्त 2021 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया ई-श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। इस पोर्टल का लक्ष्य असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच को सरल बनाया जा सके।

ई-श्रम पोर्टल की मुख्य विशेषताएं:

- पंजीकरण:** श्रमिक प्रक्रिया के माध्यम से पोर्टल पर सरलता से पंजीकरण कर सकते हैं, जिसमें उन्हें अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण प्रदान करना होगा।
- लाभ:** पंजीकृत श्रमिकों को पेंशन, मृत्यु बीमा और अक्षमता की स्थिति में वित्तीय सहायता सहित विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि होती है।

पात्रता मानदंड:

- ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण हेतु श्रमिकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
 - » आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
 - » आधार कार्ड से जुड़ा एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए।
 - » आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

हीरे का चूर्ण सौर विकिरण प्रबंधन में सहायक

संदर्भ: हाल ही में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक हालिया शोध में हीरे के चूर्ण को सौर विकिरण प्रबंधन (Solar Radiation Management -SRM) के लिए प्रभावी पदार्थ के रूप में उजागर किया है।

- शोध में सात अलग-अलग यौगिकों की तुलना की गई और निष्कर्ष निकाला गया कि हीरे सौर विकिरण को परावर्तित करने के लिए सबसे कुशल हैं। शोधकर्ताओं ने सालाना पाँच मिलियन टन हीरे के चूर्ण को

Face to Face Centres



25 October 2024

ऊपरी वायुमंडल में छिड़कने की एक महत्वाकांक्षी योजना का प्रस्ताव किया है, जिससे तापमान में लगभग 1.6 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है।

हीरे के चूर्ण (Diamond Dust) के बारे में:

- भू-इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, हीरे का चूर्ण ऊपरी वायुमंडल, विशेष रूप से समताप मंडल में छिड़कने के लिए प्रस्तावित माइक्रोन आकार के छोटे हीरे के कणों को संदर्भित करता है। इस अभिनव दृष्टिकोण का उद्देश्य सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करना और पृथ्वी के ताप को कम करने में योगदान देना है।

हीरे के चूर्ण के मुख्य गुण:

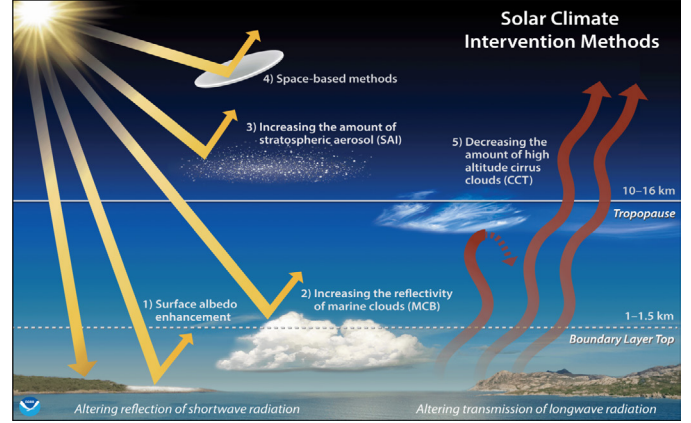
- उच्च एल्बिडो (परावर्तन):** हीरे में सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की एक उल्लेखनीय क्षमता होती है, जो उन्हें सौर विकिरण प्रबंधन (SRM) के लिए अत्यधिक प्रभावी बनाती है।
- स्थायित्व:** हीरे के कणों की मजबूत प्रकृति उन्हें विभिन्न वायुमंडलीय स्थितियों का सामना करने की अनुमति देती है।
- कम विषैले:** रासायनिक रूप से निष्क्रिय होने के कारण, हीरे पर्यावरणीय जोखिमों को कम करते हैं, जो पारंपरिक रूप से SRM के लिए मानी जाने वाली अन्य सामग्रियों के लिए एक सुरक्षित विकल्प प्रस्तुत करते हैं।

जियोइंजीनियरिंग:

- जियोइंजीनियरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए हस्तक्षेप किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का मुकाबला करना है। इसमें दो मुख्य रणनीतियाँ शामिल हैं:
 - » **सौर विकिरण प्रबंधन (Solar Radiation Management - SRM):** यह रणनीति वैश्विक तापमान को कम करने के लिए पृथ्वी से दूर सौर विकिरण को परावर्तित करने पर केंद्रित है।
 - » **कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन (Carbon Dioxide Removal - CDR):** यह दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का प्रयास करता है।

सौर विकिरण प्रबंधन (Solar Radiation Management - SRM):

- सौर विकिरण प्रबंधन (SRM) जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इसमें सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने से रोकने के लिए वायुमंडल या अंतरिक्ष में परावर्तक सामग्री का उपयोग किया जाता है। यह अवधारणा प्राकृतिक घटनाओं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोटों से प्रेरित है। उदाहरण के लिए, 1991 में माउंट पिनातुबो के विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड निकलने से ऐसे कण बने, जिन्होंने सूर्य की रोशनी को परावर्तित किया। इससे वैश्विक तापमान में अस्थायी रूप से 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई।



डायमंड डस्ट बनाम अन्य SRM सामग्री:

- ऐतिहासिक रूप से, सौर विकिरण प्रबंधन (SRM) के लिए सल्फर, कैल्शियम, और सोडियम क्लोराइड जैसी विभिन्न सामग्रियों पर विचार किया गया है। प्रत्येक सामग्री के अपने विशेष लाभ और सीमाएँ होती हैं। हालांकि, हीरे अपने अद्वितीय परावर्तक गुणों के कारण इन सामग्रियों से भिन्न हैं। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि हीरे का चूर्ण सौर विकिरण के प्रबंधन के लिए एक अधिक प्रभावी और टिकाऊ विकल्प प्रदान कर सकता है।

कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की तकनीकें:

- विभिन्न तकनीकें वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा सकती हैं:
 - » **कार्बन कैप्चर और सीक्वेट्रेशन (Carbon Capture and Sequestration - CCS):** औद्योगिक स्रोतों से CO₂ उत्सर्जन को कैप्चर करता है और उन्हें भूमिगत संग्रहीत करता है।
 - » **कार्बन कैप्चर और उपयोग (Carbon Capture and Utilization - CCU):** औद्योगिक प्रक्रियाओं में कैप्चर की गई CO₂ का उपयोग करता है।
 - » **डायरेक्ट एयर कैप्चर (Direct Air Capture - DAC):** परिवेशी वायु से सीधे CO₂ निकालता है।
- जबकि ये तकनीकें वायुमंडलीय CO₂ के स्तर को कम करने में भूमिका निभा सकती हैं, वे मापनीयता और लागत-प्रभावशीलता के संबंध में चुनौतियों का सामना करती हैं।

कार्बन कैप्चर तकनीकों के साथ चुनौतियाँ:

- जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्बन कैप्चर और सीक्वेट्रेशन (CCS) पर अत्यधिक निर्भर रहना अव्यावहारिक और महंगा साबित हो सकता है। अनुमान हैं कि जलवायु लक्ष्यों को मुख्य रूप से CCS के माध्यम से पूरा करने की लागत 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकती है, जिससे अक्षय ऊर्जा पर अधिक ध्यान केंद्रित करना आवश्यक हो सकता है।
- इसके अतिरिक्त, कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) के

Face to Face Centres



25 October 2024

लिए सुरक्षित भंडारण स्थलों की खोज में कई चुनौतियाँ सामने आती हैं, जैसे कि भंडारण स्थलों की उपलब्धता और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना।

भारत में साइबर धोखाधड़ी

संदर्भ: हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत को साइबर अपराध के कारण अगले वर्ष 1.2 लाख करोड़ से अधिक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

- यह आंकड़ा देश में साइबर अपराध की गतिविधियों के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता और भेद्यता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह संभावना है कि यह आर्थिक क्षति भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 0.7% हिस्सा प्रभावित कर सकती है।

धोखाधड़ी नेटवर्क में वृद्धि:

- दक्षिण पूर्व एशिया में धोखाधड़ी नेटवर्क का उदय, जोकि कॉल सेंटर की भांति कार्य करते हैं, घोटालों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। इन स्थानों से काम करने वाले लोग पूरे देश में अनजान पीड़ितों को ठगने के लिए भारतीय मोबाइल नंबरों का सहारा लेते हैं।

साइबर धोखाधड़ी में प्रमुख योगदानकर्ता:

- साइबर धोखाधड़ी में एक महत्वपूर्ण कारक फर्जी बैंक खातों का प्रसार है, जिनका उपयोग अक्सर अवैध लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि साइबर धोखाधड़ी में खोए गए अधिकांश धन को भारत से बाहर स्थानांतरित किया जाता है, जिसमें से कई फ्रॉड चीन, कंबोडिया और म्यांमार की संस्थाओं से जुड़े हैं।

धोखाधड़ी के चिंताजनक आँकड़े:

- जांच एजेंसियाँ प्रतिदिन लगभग 4,000 फर्जी बैंक खातों (Mule Accounts) की पहचान कर रही हैं। इस वर्ष की पहली छमाही में, गृह मंत्रालय के साइबर अपराध पोर्टल और हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज साइबर अपराध शिकायतों में कुल 11,269 करोड़ के नुकसान की सूचना मिली है।
- यह आंकड़ा साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मुद्दे का सामना करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

एटीएम और वैश्विक धोखाधड़ी:

- इसके अतिरिक्त, देश भर में 18 एटीएम हॉटस्पॉट की पहचान की गई है जहाँ धोखाधड़ी से निकासी हुई है। दुबई, हांगकांग, बैंकॉक और रूस जैसे स्थानों पर विदेशी एटीएम से नकदी निकाले जाने की भी रिपोर्ट मिली है, जिससे साइबर अपराध से निपटने के प्रयास और जटिल हो गए हैं।

साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए भारत की पहल:

- भारत ने लगभग 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करने और 2.26 लाख मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करके साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कदम उन कनेक्शनों के खिलाफ है, जोकि जाली दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त किए गए थे या जिनका साइबर अपराध के लिए दुरुपयोग किया गया।
- केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय की अगुवाई में इस पहल का उद्देश्य साइबर शिकायतों में वृद्धि को संबोधित करना है, जिसमें जनवरी 2023 से अब तक 1 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

लागू किए गए प्रमुख उपाय:

- सिम कार्ड के लिए केवाईसी प्रोटोकॉल:** दूरसंचार विभाग (DoT) ने दुरुपयोग को रोकने के लिए सिम कार्ड खरीद के लिए सख्त 'नो योर कस्टमर' (KYC) प्रोटोकॉल लागू किए हैं।
- नकली कॉल को ब्लॉक करना:** DoT ने भारतीय मोबाइल नंबर दिखाने वाली इनकमिंग अंतर्राष्ट्रीय नकली कॉल को ब्लॉक करना अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में, ऐसी 35% कॉल पहले से ही ब्लॉक की जा रही हैं और इसका पूर्ण कार्यान्वयन 31 दिसंबर, 2024 तक होने की अपेक्षा है।
- साप्ताहिक रिपोर्टिंग:** दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को हांगकांग, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस और म्यांमार सहित दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में रोमिंग करने वाले भारतीय मोबाइल नंबरों पर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।
- एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई:** राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को पॉइंट-ऑफ-सेल एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का कार्य सौंपा गया है, जो सिम कार्ड बेचते हैं और जिनका उपयोग बाद में दक्षिण-पूर्व एशिया में घोटाले के संचालन में किया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** इस पहल में साइबर अपराधों से निपटने के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संयुक्त प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग करने के उपाय शामिल हैं।

भविष्य की योजनाएँ:

- गृह मंत्रालय (MHA) फर्जी खातों (Mule Accounts) के संचालन को रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने हेतु केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ बैठक आयोजित करने की योजना बना रहा है। बैंकों को असामान्य लेनदेन की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश दिया गया है, विशेषकर उन खातों में जिनमें कम शेष राशि है या जो वेतनभोगी व्यक्तियों के हैं।

Face to Face Centres



25 October 2024

पाँवर पैकड न्यूज

भूरे बौने (Brown Dwarf)

- हाल ही में एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स और नेचर में प्रकाशित हुए लेख में शोधकर्ताओं ने यह खोज की है कि 1995 में पाया गया एक भूरा बौना वास्तव में दो है जो एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं।
- ग्लोज 229Ba और ग्लोज 229Bb नामक ये दो भूरे बौने एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा हैं, जिसका अर्थ है कि वे गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हैं। ये एक छोटे तारे की परिक्रमा करते हैं और लेपस नक्षत्र में 19 प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं।
- भूरे बौने वे पिंड हैं जो ग्रहों से बड़े लेकिन तारों से छोटे होते हैं। उनके पास तारों की तरह परमाणु संलयन शुरू करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान नहीं होता, लेकिन वे ग्रहों की तुलना में अधिक विशाल होते हैं।
- ग्लोज 229Ba का द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान से 38 गुना है और ग्लोज 229Bb का द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान से 34 गुना है। ये दो भूरे बौने एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, हर 12 दिनों में एक पूरी परिक्रमा करते हैं।
- यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भूरे बौने दुर्लभ हैं और इस प्रकार की प्रणाली में उन्हें खोजने से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि ये वस्तुएं कैसे बनती हैं।



18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में होगा

- ओडिशा में 8 से 10 जनवरी, 2025 के बीच भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित होगा।
- मुख्यमंत्री मोहन चरण मांडी ने विदेश मंत्रालय से प्राप्त इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
- प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के 9 जनवरी, 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की स्मृति में मनाया जाता है।
- प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए भारत 2003 से इस दिवस का आयोजन करता आ रहा है। पिछला प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न हुआ था।



एशियाई विकास बैंक (ADB) में इजराइल की सदस्यता

- हाल ही में, इजराइल आधिकारिक तौर पर एशियाई विकास बैंक (ADB) में इसके 69वें सदस्य और 20वें गैर-क्षेत्रीय सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। जापान ने जनवरी 2022 में ADB की सदस्यता के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया। ADB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 14 अप्रैल, 2022 को संकल्प संख्या 414 के माध्यम से इजराइल की सदस्यता को मंजूरी दी थी।
- एक नए सदस्य के रूप में, इजराइल को अपने विकास परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण और विशेषज्ञता तक पहुंच प्राप्त होगी, साथ ही क्षेत्रीय पहलों में शामिल होने और अन्य सदस्य देशों के साथ सहयोग करने के अवसर भी मिलेंगे।
- एशियाई विकास बैंक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए समर्पित है, जिसमें अत्यधिक गरीबी को खत्म करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- 1966 में स्थापित, ADB में वर्तमान में 69 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशिया-प्रशांत क्षेत्र से हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मांडलुयोंग में है।



Face to Face Centres



लुओंग कुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति

- 21 अक्टूबर को, 15वीं नेशनल असेंबली (एनए) के दौरान लुओंग कुओंग को 2026 तक के कार्यकाल के लिए वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। कुओंग, जो वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीवी) की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और इसके सचिवालय के स्थायी सदस्य हैं, को सत्र में उपस्थित सभी 440 प्रतिनिधियों से सर्वसम्मति से समर्थन मिला, जो कुल प्रतिनिधियों का 91.67% प्रतिनिधित्व करते हैं।
- वह टोह लैम का स्थान लेंगे, जिन्हें अगस्त में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया था। महासचिव का पद वियतनाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जबकि राष्ट्रपति पद काफी हद तक औपचारिक होता है, जो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिलना शामिल होता है। फाम मिन्ह चीन्ह वर्तमान में वियतनाम के प्रधान मंत्री हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है और इसकी मुद्रा वियतनामी डॉंग है।



Face to Face Centres

